

घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...



www.ghatatighatana.com

अम्बिकापुर,तर्ष 22,अंक - 110- गुरुवार 19- फरवरी 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये

RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डक पंजीकरण क्र. 13/Surguja DN/ 2026-2028

सक्षिप्त समाचार

राहुल देश की सुरक्षा के लिए खतरा..उनके नक्सलियों से रिश्ते,संसद में उनका बर्ताव बचकाना : किरण रिजिजू



नई दिल्ली, 18 फरवरी 2026। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन गए हैं। वे भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हैं। वे नक्सलियों, उग्रवादियों और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते हैं। रिजिजू ने ये बातें न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहीं। रिजिजू ने आगे कहा कि संसद में राहुल का बर्ताव बचकाना और गैर-जिम्मेदाराना है। एक लीडर ऑफ ओपोजिशन पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है। संसद के बाहर जाकर लोगों को देशद्रोही कहना,ड्रामा वाले सिट-इन करना और एक अनपब्लिशड किताब लहराना। यह सब बच्चों जैसा बर्ताव है। हमने भारत के इतिहास में ऐसा लीडर ऑफ ओपोजिशन कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ संसद में हंगामा करना है। कांग्रेस कहती है कि हम उन्हें बोलने नहीं देते। लेकिन जैसे ही वे (राहुल) अंदर आते हैं। हंगामा,बैनर और नारेबाजी शुरू हो जाती है।

नड्डा ने ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात...



नई दिल्ली, 18 फरवरी 2026। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्जेंडर पाडिल्हा से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों के बीच सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने और चिकित्सा उत्पाद वित्तीय एवं डिजिटल स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान सभी के लिए सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा पर सार्थक चर्चा हुई। स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहन और मजबूत सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। नड्डा ने ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री को ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में आमंत्रित करते हुए कहा कि ब्राजील के साथ निरंतर सहयोग की आशा है और आगामी ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के लिए एलेक्जेंडर पाडिल्हा का भारत में स्वागत है।

सैनिक विकलांगता पेंशन पर कर लगाना अनुचित : कांग्रेस

नई दिल्ली, 18 फरवरी 2026। कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के कर्मियों की विकलांगता पेंशन पर कर लगाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार ने 28 फरवरी तक यह फैसला वापस नहीं लिया तो एक मार्च को पार्टी कार्यक्रमों जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगा।कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभागे के प्रमुख कर्नल रोहित चौधरी (सेवानिवृत्त) ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि देश में करीब 2 लाख विकलांग सैनिक हैं, जबकि 50 लाख के आसपास सर्विंग और पूर्व सैनिक तथा युद्ध विधवाएं हैं।

विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना ने वैश्विक साझेदारी के साथ दिखाई समुद्री ताकत राष्ट्रपति मुर्मु ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू देखकर समुद्री परंपराओं पर भरोसा जताया

नई दिल्ली, 18 फरवरी 2026। भारत ने 1971 के युद्ध में जिस जगह में पाकिस्तान की पनडुब्बी गाली को डुबो दिया था,वहीं एक बार फिर इतिहास की गूंज सुनाई दी। विशाखापत्तनम के उसी ऐतिहासिक किनारे पर बुधवार को भारतीय नौसेना ने अपनी समुद्री ताकत, व्यावसायिकता और वैश्विक साझेदारी का प्रदर्शन किया है। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू को देखा और भरोसा जताया कि इस फ्लीट रिव्यू में शामिल सभी नौसेनावृत्त मिलकर समुद्री को दुनिया भर के विकास, खुशहाली और पूरी भलाई के रास्ते के तौर पर आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू समुद्री परंपराओं के लिए देशों के बीच एकता, भरोसा और सम्मान दिखाता है। समुद्री के साथ भारत का रिश्ता गहरा और हमेशा रहने वाला रहा है। सदियों से ये समुद्र भारत के लिए कॉमर्स,कनेक्शन और कल्चरल लेन-देन के रास्ते रहे हैं। उन्होंने



कहा कि समुद्री क्षेत्र समेत इंटरनेशनल रिश्तों को लेकर भारत का नजरिया वसुधैव कुटुम्बकम् या दुनिया एक परिवार है की हमारी सोच को दिखाता है। उन्होंने सभी भारतीयों की ओर से मित्र देशों की नौसेनाओं के अधिकारियों और नाविकों को बधाई देते हुए कहा कि आप अपनी सेवाओं से अपने देशों की सबसे अच्छी परंपराओं को दिखाते

हैं। नौसेना के कैप्टन विवेक मधवाल ने बताया कि यह भारत में किया गया तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है। आज हमने इस समुद्री समीक्षा में 70 से ज्यादा प्लेटफॉर्मों को हिस्सा लेते देखा है, जिसमें 18 दूसरे देशों के 19 जहाजों के साथ ही भारतीय तटरक्षक बल और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जहाज शामिल हैं। इस साल भारत के फ्लीट

रिव्यू में पहली बार देसी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रान्त हिस्सा ले रहा है। हमने मोबाइल कॉलम में देसी कलवरी-क्लास सबमरीन को भी हिस्सा लेते देखा है। इसके अलावा भारत में डिजाइन और बनाए गए हमारे कई प्लेटफॉर्मस ने हिस्सा लिया है, जिनमें डिस्टॉयंग,फ्रिगेट,एएसडब्ब्ल्यू सीलो वाटर क्राफ्ट,सर्वे वेसल और डाइविंग सपोर्ट वेसल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि फ्लाइंगपास्ट के जरिये नौसेना की हवाई ताकत का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें फाइटर, ट्रेनर, हेलीकॉप्टर और लंबी दूरी के मरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट रहे। इन सभी ने इस बार इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया है। कैप्टन मधवाल ने बताया कि विशाखापत्तनम में तीन बड़े कार्यक्रम इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास 'मिलन' और नौसेना प्रमुखों के कॉन्क्लेव के साथ भारत ऐतिहासिक समुद्री मेलजोल का एक अहम हिस्सा बन रहा है। इन कार्यक्रमों में 72 देशों के करीब 72 प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं।

चुनाव आयोग का ऐलान....राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव

इनमें 25 सीटें विपक्ष,एनडीए की 12,पवार,सिंधवी का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा...

नई दिल्ली, 18 फरवरी 2026। चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें 12 एनडीए के पास हैं,25 पर विपक्ष का कब्जा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 7,तमिलनाडु की 6 और पश्चिम बंगाल-बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। शरद पवार, रामदास अठावल,कणिमोड़ी, तिरुचि शिवा,राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी।

ऐसे होता है राज्यसभा चुनाव

राज्यसभा सांसदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया दूसरे चुनावों से काफी अलग है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से



चुने जाते हैं यानी जनता नहीं बल्कि विधायक इन्हें चुनते हैं। चुनाव हर दो साल में होते हैं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर होते हैं। राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 245 हैं। इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और 12 सदस्यों को

राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, ये पहले से ही तय होता है। वोटों की संख्या का कैलकुलेशन कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर होता है। इसमें एक विधायक की वोट की वैल्यू 100 होती है।

बैलेट पेपर पर खास पेन से होगी वोटिंग...

चुनाव आयोग ने कहा है कि वोट डालते समय केवल रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से दिए गए तय मानक का वाईलेट रंग का स्केच पेन ही इस्तेमाल होगा। किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।

महाराष्ट्र की 7 सीटों के उद्घरण से फॉर्मूला समझते हैं...

राज्यसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित संख्या में मतों की आवश्यकता होती है, जिसे जीतने का कोटा कहा जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 विधायक हैं। खाली हो रही सीटें 7 हैं।

उत्तर प्रदेश...2027 में बसपा अकेले दम पर लड़ेगी चुनाव : मायावती

लखनऊ, 18 फरवरी 2026। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। वह किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन से बसपा से नुकसान होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे भ्रामक खबरों पर ध्यान न देकर पार्टी को मजबूत करने में अपना सहयोग दें। बसपा प्रमुख मायावती ने एक पत्रकारवार्ता में कहा है कि मीडिया में चर्चा है कि आगामी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बसपा गठबंधन में लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह विशुद्ध रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को गुमराह करने के लिए फेंक न्यूज चलवाई गई हैं। यह बिल्कुल गलत, झूठ और मगपूत खबर है। ऐसे में नेताओं के साथ-साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भरके अपना मजाक खुद उड़ाने से बचना चाहिए। मायावती ने कहा कि वह एक बार नहीं बल्कि



हर बार पार्टी की बैठक में यहां तक बोते नौ अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित विशाल रैली में भी इसकी खुली घोषणा की थी कि बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन कुछ लोग और मीडिया भी इनकी धिनीनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की गलत खबर प्रचारित करके अपना समय और छवि दोनों बर्बाद कर रहे हैं। इस पर लोगों को बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मायावती ने कहा कि बसपा के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले पूरे जी-जान से लगे हुए हैं। जिस पर से उन लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की साजिश करते रहते हैं।

स्पेन और फिनलैंड के राष्ट्रध्यक्ष से मिले पीएम मोदी बोले...भारत-यूरोप एफटीए से सुनहरे युग की शुरुआत

नई दिल्ली, 18 फरवरी 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्पेन के राष्ट्रपति पेद्रो सांचेज और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटर्री ओपो के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने भारत-यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) को भारत-यूरोप संबंधों में स्वर्ण युग लाने वाला बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्पेन के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक में दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने, खासकर रक्षा, सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 2026 को भारत और स्पेन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें संस्कृति, पर्यटन और एआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मोदी ने बताया कि इस दौरान भारतीय और स्पेनियन विश्वविद्यालयों की बड़ी प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगी, जो लोगों को जोड़ने में मदद करेगी।

पीएम मोदी और सांचेज के बीच बैठक

पीएम मोदी और सांचेज ने पर्यटन,व्यापार, निवेश,तकनीक,नवाचार,जलवायुऔर नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा,अंतरिक्ष, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने स्पेनियन विश्वविद्यालयों और संस्थानों को एसटीईएम और तकनीकी क्षेत्रों में भारत में कैम्पस खोलने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही, दोनों नेताओं



भारत-यूरोप संबंध पर क्या बोले पीएम मोदी

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूरोपीय एफटीए से भारत और स्पेन के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों के लिए नए अवसर खुलेंगे। दोनों नेताओं ने टाटा-एयरबस सहयोग के तहत सी-295 परिवहन विमान की अंतिम असेंबली लाइन की सफलता का भी स्वागत किया। उन्होंने भारत-स्पेन डुअल ईंटर ऑफ कल्वर,टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने सह-निर्माण और सह-उत्पादन आधारित रक्षा सहयोग को भी भविष्य की दिशा बताया। बता दें कि स्पेन के राष्ट्रपति इस आधिकारिक दौरे पर 18 से 19 फरवरी तक भारत में हैं। सांचेज ने समिट के महत्व को हाइलाइट करते हुए कहा कि इसके परिणाम वैश्विक एआई गवर्नंस को आकार देने में मदद करेंगे। उन्होंने शिक्षा में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की, खासकर भारत की नई शिक्षा नीति के तहत।

ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग,और स्पेन के भारत-प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने की बात पर भी चर्चा की।

पायजामे की डोरी खोलना रेप का प्रयास माना

जाएगा,सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली, 18 फरवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक विवादित फैसले को बदल दिया है इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पायजामे का नाड़ा खोलना बलात्कार की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित फैसले को पलटने का फैसला किया है, जिसमें कहा गया था कि एक बच्ची के ब्रेस्ट को पकड़ना,उसके पायजामे का नाड़ा खोलना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना रेप या रेप की कोशिश नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ी इलाजगी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने जस्टिस जॉयमाल्या

बागची और एनबी अंजारिया के साथ कहा कि यौन अपराधों के मामलों में फैसले के लिए कानूनी तर्क और सहनुभूति दोनों की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ब्रेस्ट पकड़ना और पायजामे का नाड़ा खींचना 'रेप की कोशिश' के बराबर है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ये सिर्फ 'रेप करने की तैयारी' है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एन वी अंजारिया की बेंच ने कहा कि विवादित ऑर्डर को 'क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के तय सिद्धांतों के साफ तौर पर गलत इस्तेमाल' की वजह से रद्द किया जाता है।

शिक्षा,स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकता,यह सबको सुलभ होना चाहिए : मोहन भागवत

लखनऊ, 18 फरवरी 2026। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने शिक्षा और स्वास्थ्य को मूलभूत आवश्यकता बताते हुए कहा कि यह सबके लिए सुलभ होना चाहिए। यह व्यवस्था नहीं हो सकते। डॉ. भागवत ने बुधवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में शोधार्थी छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में कहा कि पश्चिम के लोगों ने शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया। हमारी शिक्षा व्यवस्था हटाकर अपनी थोपी, जिससे उन्हें काम करने के लिए 'काले अंग्रेज' मिल जाएं। अंग्रेजों ने जो बिगाड़ है उसको ठीक करना ही होगा। उन्होंने कहा कि संघ का कार्य देश को परम वैभव सम्पन्न बनाना है। मैं और मेरा परिवार ही सबकुछ है, यह न सोच कर पूरे देश के लिए सोचना होगा। संघ समाज की एकता और गुणवत्ता की चिंता करता है। संघ को समझना है तो संघ में आकर कर देखिये। संघ को पढ़ कर नहीं समझा जा सकता है। संघ को सम्पूर्ण हिन्दू समाज को संगठित करने वाला एक ही काम करना है। संघ किसी के विरोध में नहीं है। संघ को लोकप्रियता, प्रभाव और शक्ति नहीं चाहिए। सरसंघचालक डॉ. भागवत ने कहा कि भारत की दिशा और दशा बदलने में शोध की बड़ी भूमिका है।



सत्यपरक बातें सामने आनी चाहिए। अज्ञानता से भारत को हम समझ ही नहीं पाएंगे। उन्होंने शोधार्थियों छात्रों से कहा कि जो भी शोध करें उसे उत्कृष्ट रूप से, प्रामाणिकता पूर्वक,तन-मन-धन से, निःस्वार्थ भाव से, देश के लिए करें। उन्होंने कहा कि संघ को लेकर बहुत दुष्प्रचार होता है। शोधार्थियों को सत्य सामने लाना चाहिए। वैश्वीकरण के विषय पर उन्होंने कहा कि यह कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। आज वैश्वीकरण का मतलब बाजारीकरण से है,जो खतरनाक है। हम वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करते हैं। यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन संयमित होना चाहिए,उपभोगवादी नहीं।

अंबिकापुर में देह व्यापार का भंडाफोड़.... पुलिस ने नेटवर्क चलाने वाले दंपती को किया गिरफ्तार

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 18 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में लंबे समय से संचालित हो रहे एक बड़े देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक संचालक दंपती को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस की यह कार्रवाई शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवैध धंधों पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। काफी समय से पुलिस की खुफिया विंग इस गिरोह की गतिविधियों पर नजर रख रही थी, जिसके बाद पुख्ता सबूत मिलने पर दबिश दी गई।



व्यापक कार्रवाई का हिस्सा: अब तक 20 से अधिक आरोपियों पर गिर चुकी है गाज

अंबिकापुर पुलिस इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए पिछले काफी समय से अभियान चला रही है। ताजा गिरफ्तारी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे मामले में अब तक गिरोह के करीब 20 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस की टीम ने लगातार निगरानी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर जाल बिछाया, जिसमें यह संचालक दंपती फंस गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने नेटवर्क से जुड़े कई अन्य खुलासे भी किए हैं।

लालच देकर अंबिकापुर लाया जाता था और फिर उन्हें इस दलदल में धकेल दिया जाता था। गिरोह की कार्यप्रणाली बेहद शांति थी; किसी को शक न हो, इसके लिए

युवतियों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए ऑटो रिक्शा का सहारा लिया जाता था। इस तरह वे सामान्य परिवहन की आड़ में अपने अवैध कारोबार को बेखोफ अंजाम दे रहे थे।

कानून का कसा शिकंजा पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज

यह पूरी कार्रवाई नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार दंपती के खिलाफ 'अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956' की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि शहर के किसी भी होटल, लॉज या आवासीय क्षेत्र में इस तरह की अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन युवतियों को लाने कोई गिरोह तो सक्रिय नहीं है।

उन मागीदारी की अपील... सद्विध गतिविधियों की सुचना देने के लिए हेल्पलाइन जारी

पुलिस प्रशासन ने इस सफल कार्रवाई के बाद आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। पुलिस का कहना है कि शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए नागरिकों की सतर्कता अनिवार्य है। यदि किसी भी मोहल्ले या व्यावसायिक परिसर में सद्विध लोगों का आना-जाना या असामान्य गतिविधियां नजर आए, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने विश्वास दिलाया है कि सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। फिलहाल, पकड़े गए दंपती से पूछताछ के आधार पर पुलिस आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे करने का दावा कर रही है।

बोर्ड परीक्षा के दौरान डीजे पर सख्ती पुलिस ने संचालकों की ली बैठक



—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 18 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा शुरू है और छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से होनी है। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरगुजा पुलिस ने जिले में डीजे संचालन और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर सख्ती बढ़ा दी है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में थाना कोतवाली में जिले के सभी डीजे संचालकों, मैरिज गार्डन संचालकों और होटल प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि किसी भी सामाजिक, धार्मिक आयोजन, रैली, जुलूस या कार्यक्रम में डीजे संचालन से पहले विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साउंड सिस्टम की आवाज तय मानकों के भीतर रखी जाएगी। पुलिस

ने निर्देश दिए कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा। तय समय के बाद डीजे बजाने पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उपकरण जब्त किए जाएंगे। डीजे संचालकों को रजिस्टर संधारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें अनुमति पत्र, आयोजनकर्ता की पहचान और अन्य जानकारी लिखित रूप में दर्ज करना होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल संपर्क किया जा सके। बैठक में डीजे संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई कि किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गीत नहीं बजाए जाएं। सभी संचालकों ने दिशा-निर्देशों का पालन करने की सहमति दी। बैठक में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक ललन गुप्ता, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह सहित जिलेभर के डीजे संचालक, मैरिज गार्डन एवं होटल प्रबंधक उपस्थित रहे।

चोरी के मामले में खरीदार सहित चार आरोपी गिरफ्तार

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 18 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर खुर्द गोरसीडबरा में अज्ञात चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर करीब डेढ़ लाख रुपए मूल्य के आभूषण और अन्य सामान चोरी कर लिया था। मामले में गांधीनगर पुलिस ने तीन आरोपियों और एक खरीदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी और चोरी का माल खरीदने के आरोप में कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, अनिल दास 4 फरवरी को घर में ताला बंद कर परिवार सहित जगन्नाथ पुरी दर्शन करने गए थे। 5 फरवरी को उनके भाई सुदामा ने फोन कर घर में चोरी होने की सूचना दी। वापस लौटने पर सामान का मिलाप करने पर पता चला कि अलमारी में रखी सोने की चेन, चांदी का कड़ा, सोने का लॉकेट, नथनी, चांदी की घायल और दो सोने की अंगुठियां चोरी हो गई थीं। अनिल ने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच कर रही थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने संदेही अतुल तिग्गा उर्फ अक्की (20 वर्ष), सत्यादीप



तिग्गा उर्फ टका (21 वर्ष) और राजा लकड़ा (20 वर्ष), सभी निवासी विष्णुपुर खुर्द गोरसीडबरा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों ने चोरी किए गए आभूषण ब्रह्मपरा निवासी कमल सोनी को बेचने की बात बताई। पुलिस ने तीनों आरोपियों और खरीदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

होली से पहले किसानों को 3100 रुपये प्रति किचंटल की अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के किसान हितैषी निर्णय से किसानों में उत्साह

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 18 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति किचंटल की दर से अंतर राशि का भुगतान होली पर्व से पूर्व एकमुश्त किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए इस निर्णय से जिले के किसानों में उत्साह और हर्ष व्याप्त है।

किसानों को मिलेगी बड़ी आर्थिक राहत : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के इस किसान हितैषी निर्णय का स्वागत करते हुए लखनपुर विकासखंड के ग्राम कोसगा के किसान श्री पहलूरा ने हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष उन्होंने लगभग 72 किचंटल धान समर्थन मूल्य पर बेचा है, जिसकी राशि उन्हें प्राप्त हो चुकी है। अब



अंतर की राशि होली से पहले मिलने की घोषणा से वे अत्यंत खुश हैं। उन्होंने कहा कि होली के बाद विवाह-शादी का सीजन प्रारंभ हो जाएगा, ऐसे में यह राशि पारिवारिक

जिले के 52 हजार से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत, प्रदेश भर में किसानों को इस निर्णय का सीधा लाभ मिलेगा। जिले में 52,553 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया है, उन्हें अब अंतर की राशि उनके बैंक खातों में एकमुश्त प्राप्त होने से किसानों के चेहरे पर खुशी एवं रौनक आयेगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के किसान हितैषी निर्णय से अन्नदाताओं को उनके पसीने की पूरी कीमत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। होली से पहले अंतर राशि का भुगतान होने से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही स्थानीय बाजारों में रौनक बढ़ेगी।

आवश्यकताओं और सामाजिक दायित्वों के कार्य में सहायक होगी। श्री पहलूरा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार

व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में अत्यंत सरहनीय है और इससे किसानों में उत्साह का माहौल है।

ऑनलाइन निवेश और टूर पैकेज के नाम पर ठगी दो मामलों में कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया अपराध, जांच जारी



—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 18 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

शहर में ठगी के दो अलग-अलग मामलों में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक मामले में टेलीग्राम ग्रुप के जरिए ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर 80 हजार रुपए ठगे गए, जबकि दूसरे मामले में टूर पैकेज के नाम पर 18 हजार रुपए लेकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस के अनुसार भगत सिंह वाई, गुदरी चौक निवासी रविश कुमार वर्मा उर्फ सोनू ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित जूता-चप्पल ट्रेडिंग का काम करता है। रविश ने बताया कि 9 सितंबर 2025 को उसे मोबाइल के माध्यम से टेलीग्राम पर डीएफबीएन नामक ग्रुप से जोड़ा गया था। ग्रुप के एडमिन ने ऑनलाइन निवेश के टास्क पूरे करने पर अधिक लाभ दिलाते का प्रलोभन दिया। इसके झांसे में आकर पीड़ित ने अलग-अलग किस्तों में करीब 80 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। बाद में लाभ नहीं मिलने पर उसे धोखाधड़ी का एहसास हुआ। उसने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरे मामले में विलक्षण कॉलोनी, घुटरापारा निवासी सोमदेव नारायण गुप्ता ने टूर के नाम पर ठगी की शिकायत की है। पीड़ित के अनुसार महाराष्ट्र निवासी शहाबाज अंसारी तथा अंबिकापुर के संजय खूटे और समीर ने रेडमास क्लब बैकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आकाशवाणी चौक स्थित होटल कृष्ण दक्ष की पहली मंजिल में कार्यालय खोला था। आरोपियों ने चार लोगों के लिए रेल व हवाई यात्रा टिकट, स्टेशन से होटल तक आने-जाने और अन्य सुविधाओं का दावा करते हुए टूर पैकेज के नाम पर 18 हजार रुपए ले लिए। पीड़ित ने यूपीआई के माध्यम से राशि संजय खूटे को ट्रांसफर की थी। इसके बाद कार्यालय बंद कर आरोपी गुपचुप तरीके से फरार हो गए। कंपनी की वेबसाइट भी बंद बताई जा रही है। संपर्क करने पर मोबाइल फोन भी बंद मिला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चरित्र संका पर पति ने पत्नी की थी हत्या... पुलिस ने हत्यारा पति के साथ सबूत मिटाने में मदद करने वाले सहयोगी को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक रिमांड पर

—संवाददाता—
बलरामपुर, 18 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले कोतवाली थाना क्षेत्र में चरित्र संका को लेकर आरोपी पति ने अपनी पत्नी की मारपीट कर हत्या कर दी थी, साक्ष्य छुपाने के लिए अपने सहयोगी के साथ मिलकर लाश को फांसी में लटकाने का आत्महत्या साबित करना चाहता था, पुलिस की तपस्वी ने हत्या की बात सामने आने पर आरोपी पति एवं सहयोगी को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 35/2026, धारा-103(1), 238, 3 (1) बी0 एन0 एस0 के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार आरोपी गुना राम पिता स्व. गेवा राम जाति चेरवा उम्र 58 वर्ष ग्राम झपरा थाना बलरामपुर जिला बलरामपुर। लखन कुम्हरिया पिता स्व. नन्का कुम्हरिया जाति कोड़ाकू उम्र 50 वर्ष, ग्राम झपरा थाना बलरामपुर जिला बलरामपुर को भेजा न्यायिक रिमांड पर।



जानकारी के अनुसार दिनांक 13.02.2026 की शाम बलरामपुर कोतवाली पुलिस ने अनिल खलखो निवासी झपरा की रिपोर्ट पर थाना बलरामपुर में मर्मा.क्र. 09/2026 धारा 194 बीएनएसएस का मर्ग इंटीमेशन चाक

कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया था। पुलिस को घटना स्थल ग्राम झपरा लातापानी के घने जंगल के पेड़ में महिला का शव फांसी के फंदे में लटका हुआ मिला था। मर्ग जांच के दौरान विधिवत शव पंचनामा किया गया, मृतिका के शरीर में

संदेहजनक गंभीर चोट खरोंच के निशान पाए जाने पर मृतिका के शव का डाक्टरों की टीम से पी.एम. कराया गया बाद पी.एम. कर्ता डाक्टरों से शार्ट पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें डाक्टर द्वारा मृतिका बंधनी पति गुना राम उम्र 50 वर्ष जाति खेवार सा. झपरा की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति का बताया गया।

मर्ग की जांच एवं टेक्निकल जानकारी के आधार पर पाया गया कि गुना राम अपनी पत्नी बंधनी के अक्सर घर से बाहर जाने के बाद कई दिनों तक घर वापस नहीं आने से चरित्र शंका होने के कारण नाराज रहता था, मृतिका दिन बुधवार को भी बलरामपुर बाजार करने गई थी जो रात में नहीं आने से दूसरे दिन गुरुवार को घर आने से नाराज था। आरोपी द्वारा दिनांक 13.02.2026 अपनी पत्नी को धक्का देकर जमीन में गिरा दिया तथा बांस के डंड, हाथ एवं पैर

से मारपीट किया गया था। मर्ग जांच में सदर धारा 103(1), 238, 3 (1) बीएनएस का अपराध घटित होना पाए जाने से आरोपी गुना राम के विरुद्ध उपरोक्त धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में आरोपी लखन कुम्हरिया के विरुद्ध गुना राम के साथ मिलकर हत्या के अपराध को छुपाने तथा मृतिका के बाँड़ी को फांसी में लटकाने में सहयोग करना पाया गया। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करने का सबूत पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी गुना राम पिता स्व. गेवा राम जाति चेरवा उम्र 58 वर्षग्राम झपरा, लखन कुम्हरिया पिता स्व. नन्का कुम्हरिया जाति कोड़ाकू उम्र 50 वर्ष, ग्राम झपरा को आज दिनांक 15.02.2026 को विधिवत न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।

अवैध रूप से भंडारित बीज जब्त कर मां महामाया कोल्ड स्टोरेज को कारण बताओ नोटिस जारी

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 18 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

कलेक्टर श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन एवं उप संचालक कृषि के निर्देशन में बीज निरीक्षक श्री सोहन लाल भगत एवं टीम के द्वारा मंगलवार को दरिमा मोड़ स्थित मां महामाया कोल्ड स्टोरेज में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्ड स्टोरेज में विभिन्न कंपनियों के मक्का, धान एवं सरसों बीज अवैध रूप से भंडारित पाए गए। कोल्ड स्टोरेज के संचालक द्वारा बताया गया कि उक्त बीज कंपनियों एवं दुकानदारों द्वारा भण्डारण किया गया है। भंडारित बीजों में कुछ बीज एक्सपायरी पाए गए थे,



जिनका आगामी खरीफ में कृषकों को वितरण ना हो इसलिए अवैध रूप से भंडारित समस्त बीज को जब्त कर अभिरोध हेतु संबंधित कोल्ड स्टोरेज के संचालक श्री रुपेश अग्रवाल के



सुपुर्द किया गया। कोल्ड स्टोरेज के संचालक को नोटिस जारी कर भण्डारित बीज किस कंपनी एवं किस व्यवसायी का है इसकी जानकारी मांगी गई है।

ग्रामीण की मौत के मामले में आरोपी एसडीएम सेंट्रल जेल शिफ्ट

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 18 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के कोरधा थाना अंतर्गत झारखंड सीमा से लगे हंसपुर क्षेत्र में अवैध बाँससाइट खनन के आरोप में हुई मारपीट से

ग्रामीण की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मुख्य आरोपी एसडीएम कृष्ण कुमार डहरिया को रामानुजगंज जेल से अंबिकापुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अन्य

आरोपी रामानुजगंज जेल में बंद हैं। शासन स्तर पर जांच के बाद आरोप सिद्ध होने पर एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है।
प्रशासनिक टीम पर मारपीट का आरोप : जानकारी के अनुसार 15 फरवरी की रात

अवैध बाँससाइट खनन की सूचना पर प्रशासनिक टीम हंसपुर गांव पहुंची थी। ग्रामीणों ने टीम पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस दौरान 62 वर्षीय राम उर्फ रामनरेश की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई।

साढ़े 28 किलो गांजा जब्त, दो अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

ओडिशा से लाकर बनारस ले जाने की थी तैयारी, बस स्टैंड के पास पकड़े गए आरोपी

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 18 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

कोतवाली पुलिस ने साढ़े 28 किलो गांजे के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर अंबिकापुर पहुंचे थे और यहां से उत्तरप्रदेश के बनारस जाने की तैयारी कर रहे थे। जब्त गांजे की कीमत करीब 4.28 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 17 फरवरी को थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा को सूचना मिली कि प्रतिष्ठा बस स्टैंड के पीछे दो युवक सफेद प्लास्टिक बोरो में गांजा खसकर ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों सद्विधों को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बोरो में 28 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में अमित शर्मा (21), निवासी चुनार, जिला मिर्जापुर (उत्तरप्रदेश) देवचंद यादव (20), निवासी कैमरू (बिहार) शामिल हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।



2.25 करोड़ का पशुपालन ऋण...93 लाख का धान प्रकरण और एक नाम बार-बार—क्या सहकारी बैंक में जवाबदेही से ऊपर ‘संरक्षण’ है?

निलंबन,एफआईआर और फिर बहाली-सहकारी बैंक में किसका संरक्षण ?

भैयाथान शाखा में करोड़ों का खेल: अजीत सिंह के कार्यकाल की परतें खोलती फाइलें

एफआईआर के बाद भी कुर्रौं बरकरार? सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल

93 लाख धान प्रकरण,2.25 करोड़ पशुपालन ऋण तक—क्या संरक्षण तंत्र के सहारे बचता रहा सिस्टम?

आधा पैसा बकाया,63 लाख त्वरित जमा—क्या जमानत की रणनीति थी यह वापसी?

सहकारी बैंक में जवाबदेही या राजनीतिक पहुंच? भैयाथान शाखा विवादों के घेरे में

—ऑकार पाण्डेय—

सूरजपुर, 18 फरवरी 2026

(घटती-घटना)।

भैयाथान-लटोरी शाखा के दस्तावेजों से उठते सवाल,बैंकिंग सिस्टम की साख दांव पर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, अंबिकापुर की भैयाथान-लटोरी शाखा पिछले कई वर्षों से विवादों में रही है, 2019 के धान खरीदी प्रकरण (करीब 93.41 लाख) से लेकर 2.25 करोड़ रुपये के पशुपालन ऋण मामले तक—हर बड़े विवाद में एक नाम बार-बार सामने आता है। तत्कालीन शाखा प्रबंधक अजीत सिंह,दस्तावेजों में एफआईआर,निलंबन और आंशिक रिकवरी दर्ज है; लेकिन पुनः बहाली और करोड़ों की लंबित वसूली बैंकिंग कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

2019: धान खरीदी में 93 लाख की अनियमितता

कलेक्टर कार्यालय,सरगुजा-अंबिकापुर के पत्राचार में धान खरीदी प्रकरण में लगभग 93.41 लाख की गड़बड़ी का उल्लेख हुआ और आवश्यक पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए गए, सवाल तब भी उठा था—क्या दौषियों पर अभियोजन चला? क्या रिकवरी पूरी हुई? यदि

■ करोड़ों की अनियमितता, स्थानांतरणों का सिलसिला और फिर बहाली—कौन बचा रहा है किसे ?

■ किसानों के भरोसे पर चोट: पशुपालन ऋण घोटाले में बैंक प्रबंधन कठघरे में

यदि ऋण ‘सही’ था तो 50% रिकवरी लंबित क्यों?

सबसे बड़ा सवाल: करीब आधी राशि आज भी बकाया क्यों है? दो वर्ष बाद भी करोड़ों की रिकवरी लंबित बताई जाती है,क्या लाभार्थियों की पात्रता और जमानत की जांच पुख्ता थी? क्या ऋण वास्तविक पशुपालकों तक पहुंचा या कागजों पर ही रहा? क्या आंतरिक ऑडिट ने जोखिम संकेतों को समय पर पकड़ा? बैंकिंग का सिद्धांत साफ है—वैध और सक्षम आश्वासनों से किस्तें नियमित आती हैं, लंबित वसूली यह संकेत देती है कि या तो वितरण प्रक्रिया में गंभीर कमी थी, या रिकवरी तंत्र ढीला रहा।

15 दिनों में 63 लाख जमा: जमानत की रणनीति?

सूत्रों के अनुसार,एफआईआर और गिरफ्तारी की आशंका के बाद सिर्फ 15 दिनों में लगभग 63 लाख जमा हुए,यह त्वरित जमा कई सवाल खड़े करती है: क्या यह जमानत/कानूनी राहत पाने की कोशिश थी? यदि इतनी राशि तुरंत जमा हो सकती है, तो शेष करोड़ों की वसूली क्यों अटकती है? क्या यह आंशिक स्वीकारोक्ति का संकेत था? यदि ऋण पूर्णतः वैध था, तो इतनी बड़ी रकम की अचानक वापसी का औचित्य क्या था?

2019 में कठोर और समयबद्ध कार्रवाई होती, तो क्या आगे के विवाद टल सकते थे?

2022-23: 2.25 करोड़ का पशुपालन ऋण प्रकरण

भैयाथान-लटोरी शाखा में पशुपालन ऋण वितरण को लेकर गंभीर शिकायतें आईं,जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितताएँ पाई गईं, 04 जनवरी 2023 को थाना झिलमिली में

आईपीसी की धाराओं 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 34 (सामूहिक मंशा) के तहत एफआईआर दर्ज हुई,27 जनवरी 2023 को निलंबन आदेश जारी हुआ,आरोपों के केंद्र में तत्कालीन शाखा प्रबंधक अजीत सिंह का नाम रहा—जिनके कार्यकाल में कथित तौर पर ऋण स्वीकृति, पात्रता सत्यापन और जमानत/मार्जिन जांच में गंभीर विसंगतियाँ सामने आईं।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 18.38 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन भटगांव में अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण को मिली गति

—संवाददाता—

सूरजपुर, 18 फरवरी 2026

(घटती-घटना)।

प्रदेश में संतुलित एवं समावेशी विकास को गति देने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण के कार्य निरंतर जारी हैं, इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र में लगभग 18.38 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत भूमिपूजन एवं प्रारंभ पूजन किया, इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक,जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विकास कार्यों को लेकर क्षेत्र में उत्साह का वातावरण देखने को मिला।

ग्राम शिवनंदनपुर में 3.41 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने ग्राम शिवनंदनपुर स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में अधोसंरचना मद अंतर्गत 3.41 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इन कार्यों में शामिल हैं, नकाना तालाब घाट निर्माण,फुटपाथ निर्माण,अटल परिसर



निर्माण,आर.सी.सी.नाली निर्माण,बी.टी. रोड निर्माण कार्य इन कार्यों के पूर्ण होने से ग्राम स्तर पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा ग्रामीणों को बेहतर आवागमन और स्वच्छता व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

14.97 करोड़ रुपए से दो प्रमुख सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण

इसके पश्चात मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े लोक निर्माण विभाग अंतर्गत आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में शामिल हुईं, जहां 14.97 करोड़ रुपए की लागत

से दो महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्यों का भूमिपूजन किया गया,इनमें शामिल हैं:भटगांव से अनरोखा मार्ग (6.00 किमी) लागत: 878.50 लाख रुपए,पकनी से चेन्द्रा मार्ग (5.60 किमी),लागत: 618.63 लाख रुपए इन सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा,जिससे व्यापार, शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर और सुरक्षित संपर्क मार्ग उपलब्ध होंगे।

मंत्री का संवोधन

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य विकास की मुख्यधारा से वंचित क्षेत्रों तक आधारभूत सुविधाएं पहुंचाना है, ताकि नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके, मंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियाव्यवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति

कार्यक्रम में वन विकास निगम अध्यक्ष रामसेवक पैकरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे,स्थानीय नागरिकों ने इन विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की अधोसंरचना को नई गति मिलेगी।

रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 2.38 लाख की ठगी,फरार आरोपी को जयनगर पुलिस ने दबोचा



—संवाददाता—

सूरजपुर, 18 फरवरी 2026

(घटती-घटना)।

रेलवे विभाग में भ्रूय (चपरासी) की नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले फरार आरोपी को जयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पूर्व में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जबकि दूसरा आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम आमगांव निवासी बालरूप सिंह ने दिनांक 04 मई 2025 को थाना जयनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सितंबर 2023 में उसके परिचित अज्जू सिंह (पिता बुहन सिंह, निवासी ठाकुरपुर थाना गांधीनगर) ने रेलवे विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर उससे 2 लाख 38 हजार 600 रुपये ले लिए। नौकरी नहीं लगने पर आरोपी ने 70 हजार रुपये वापस कर दिए,लेकिन शेष राशि लौटाने से इनकार कर दिया, प्रार्थी की शिकायत पर अपराध क्रमांक 122/2025 धारा 420, 34 भादस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

पहले एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा था फरार

पुलिस ने 06 मई 2025 को आरोपी अज्जू सिंह को गिरफ्तार किया था,पूछताछ के दौरान उसने अपने सहयोगी सुदामा दास के साथ मिलकर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया, दोनों ने मिलकर प्रार्थी एवं उसके भाई से विभिन्न माध्यमों से कुल 2,38,600 रुपये लिए थे, घटना के बाद से सुदामा दास फरार था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।

अब क्या होना चाहिए?

- समयबद्ध रिकवरी डैशबोर्ड—सार्वजनिक प्रगति रिपोर्ट।
- फॉरेंसिक ऑडिट-ऋण स्वीकृति से वसूली तक स्वतंत्र जांच।
- बहाली के आधार सार्वजनिक—बोर्ड कार्यवाही का सार।
- लाभार्थी सत्यापन/सामाजिक ऑडिट-जमीन-स्तर की पुष्टि।
- जवाबदेही तय-यदि प्रणालीगत चूक है तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई।

भरोसे की परीक्षा

यह केवल 2.25 करोड़ या 93 लाख का हिसाब नहीं—यह सहकारी बैंकिंग की साख का सवाल है। यदि आरोपों के केंद्र में रहे तत्कालीन शाखा प्रबंधक अजीत सिंह के कार्यकाल में ये प्रकरण हुए और फिर भी करोड़ों की वसूली लंबित है, तो बैंक प्रबंधन को स्पष्ट,दस्तावेज-आधारित जवाब देना होगा, क्योंकि अंततः यह किसानों का पैसा है और भरोसे पर खड़ी व्यवस्था में पारदर्शिता से बड़ा कोई संरक्षण नहीं होता।

फरार आरोपी की गिरफ्तारी

डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान फरार आरोपियों की धरपकड़ तेज की गई। इसी क्रम में थाना जयनगर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सुदामा दास (पिता बर. समल दास,उम्र 48 वर्ष, निवासी मरील बरडीपा टोला, थाना बगीचा जिला जरापुर) क्षेत्र में देखा गया है,सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अज्जू सिंह के साथ मिलकर नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। आरोपी को 17 फरवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया गया।

पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका-

इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन एवं एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैकरा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जयनगर रूपेश कुन्तल एक्का, एसआई सोहन सिंह,प्रधान आरक्षक रजिन्द्र एक्का,आरक्षक हरिशंकर सिंह, सुरेश साहू एवं अम्बिका मरावी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस की अपील

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर निजी व्यक्तियों को रकम न दें,संदेह होने पर तत्काल निकटतम थाना या पुलिस हेल्पलाइन से संपर्क करें।

मानदेय की मार, मारपीट का आरोप, न्याय की गुहार के साथ एक बार मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए कह कर... दर-दर भटकती रही पीड़िता, पर मुलाकात न हो सकी

मध्याह्न भोजन सहायिका के 21,900 रुपये बकाया, विवाद बढ़ा तो थाने-जेल तक पहुँचा मामला-दस्तावेजों से खुली कई परतें



भोजन बनाया, भुगतान नहीं मिला-मानदेय विवाद में मारपीट के आरोप

आठ महीने का बकाया, न्याय की तलाश में रसोईया दंपति

मानदेय भुगतान में देरी पर उठा विवाद, जांच के निर्देश जारी

मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी 21,900 रुपये अटके, कार्रवाई की मांग तेज

मध्याह्न भोजन व्यवस्था
ज़मीनी हकीकत

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन देना और स्कूल उपस्थिति बढ़ाना है, ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना स्थानीय महिलाओं को रोजगार का साधन भी देती है, लेकिन अक्सर सामने आने वाली समस्याएँ हैं: मानदेय में देरी, भुगतान की अस्पष्ट प्रक्रिया, ईंधन/सामग्री की राशि में कटौती या विलंब, समूह राजनीति और स्थानीय दबाव/विशेषज्ञों का कहना है कि मानदेय की कम राशि और भुगतान में देरी से काम करने वालों की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

-संवाददाता-
एमसीबी, 18 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री से मिलना है-एक उम्मीद जब स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हुई, तो पीड़िता ने आखिरी उम्मीद मुख्यमंत्री से मुलाकात को माना, जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री के जिले में प्रवास के दौरान वह अपनी समस्या लेकर पहुँची, हथ में आवेदन पत्र, आँखों में उम्मीद-उसे लगा शायद अब उसकी बात सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचेगी, लेकिन हकीकत अलग थी, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल के आसपास भारी भीड़, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रोटोकॉल था। पीड़िता आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं थी कि प्रभावशाली लोगों तक पहुँच बना सके,

वह आसपास भटकती रही, लोगों से गुहार लगाती रही-बस एक बार मिलवा दीजिए, मेरी बात सुन लेंगे...पर कोई उसे मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचा सका, कहा जाता है कि उसने कुछ स्थानीय लोगों और अधिकारियों से भी अनुरोध किया, पर औपचारिक प्रक्रिया और भीड़ के बीच उसकी आवाज दब गई।



बता दें कि एमसीबी जिले के खड़गवाँ-स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी पर आधारित है, आरोपों की निष्पक्ष जांच अभी शेष है, व्यवस्था इस मामले ने कई परतें खोल दी हैं, एक गरीब परिवार का बकाया मानदेय, स्कूल में कथित विवाद, थाने और जेल तक पहुँची बात, और प्रशासनिक

हस्तक्षेप की जरूरत, यह प्रकरण केवल 21,900 रुपये का नहीं, बल्कि सम्मान, अधिकार और जवाबदेही का भी है, यदि आरोप सत्य साबित होते हैं, तो यह व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न होगा, यदि नहीं, तो तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट होना भी उतना ही जरूरी है, अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। यह रिपोर्ट पीड़ित दौरा उपलब्ध आवेदन-पत्रों, कार्यालयीन पत्राचार और स्थानीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है, आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि एवं प्रशासनिक जांच की अंतिम रिपोर्ट आना शेष है, संबंधित पक्षों का आधिकारिक बयान प्राप्त होने पर उसे समान प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

टूटी उम्मीद, खुला दर्द-

मुख्यमंत्री से मुलाकात न हो पाने के बाद उसने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि हम गरीब लोग हैं, हमारी सुनने वाला कौन है? उसके लिए मुख्यमंत्री केवल एक पद नहीं, बल्कि न्याय की अंतिम उम्मीद थे, जब वह उम्मीद भी अधूरी रह गई, तो उसकी पीड़ा और गहरी हो गई।

वया है पूरा मामला?-

प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, ग्राम अवरार्डंड (तहसील खड़गवाँ/चिरमिरी, जिला एमसीबी/कोरिया) निवासी श्रीमती बेला बाई (नाम दस्तावेजानुसार) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन सहायिका के रूप में कार्यरत हैं, उनके पति भी उसी स्कूल में भोजन बनाने में सहयोग करते हैं, आवेदन में उल्लेख है कि, सहायिका का 8 माह का मानदेय 9,600 रुपये, पति का 4 माह का मानदेय 4,800 रुपये, लकड़ी/ईंधन मद की राशि 7,500 रुपये कुल बकाया: 21,900 रुपये आवेदिका का आरोप है कि कई बार आवेदन देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।

विवाद की चिंगारी: मानदेय की मांग और कथित टकराव

दूसरे दस्तावेज में उल्लेख है कि 15 अगस्त 2025 के आसपास विद्यालय परिसर में विवाद हुआ, आवेदिका के अनुसार, उनके पति को स्कूल के शिक्षकों द्वारा कथित रूप से काम से हटाने की बात कही गई, विरोध करने पर स्थिति बिगड़ गई और मारपीट का आरोप लगाया गया, आवेदन में यह भी दावा है कि, समूह की महिलाओं को उकसाकर उनके पति के साथ दुर्व्यवहार किया गया, शराब पीने का आरोप लगाकर थाने में बंद कराया गया, बाद में जेल भेजे जाने की बात भी कही गई, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, किंतु दस्तावेजों में इन्हें स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है।

प्रशासनिक पत्राचार: जांच के संकेत-

30 अक्टूबर 2025 को जारी एक पत्र (कार्यालय-अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण, मनेन्द्रगढ़) में कलेक्टर, जिला एमसीबी को संबोधित करते हुए मामले की जांच और मानदेय भुगतान के संबंध में कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, पत्र में उल्लेख है कि सक्षम अधिकारी नियुक्त कर जांच कराते हुए मानदेय भुगतान और आवेदन के निराकरण की जानकारी दी जाए, यह पत्र इस बात का संकेत देता है कि मामला केवल मौखिक आरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि औपचारिक स्तर पर संज्ञान लिया गया।

प्रशासन की भूमिका और संभावित कार्रवाई अब निगाहें जिला प्रशासन पर हैं, प्रमुख प्रश्न हैं:

वया 21,900 रुपये का भुगतान लंबित है?

यदि हाँ, तो देरी का कारण वया है?

मारपीट और जेल भेजे जाने के आरोपों की जांच कब तक करेगा?

वया मध्याह्न भोजन व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाएगी? यदि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हुई, तो यह मामला अन्य जिलों में भी भुगतान प्रणाली को सुधारने का आधार बन सकता है।

कानूनी पहलू

यदि मानदेय लंबित है, तो संबंधित विभाग पर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बनती है, यदि मारपीट या झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ सकता है, यदि आवेदिका या उनके पति के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो यह मानवाधिकार और श्रम अधिकार दोनों का मामला हो सकता है, हालांकि, जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा जांच पूरी नहीं होती, किसी भी पक्ष को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

व्यापक संदर्भ: सिस्टम की खामियां या व्यक्तिगत विवाद?

यह मामला केवल एक स्कूल या एक गांव तक सीमित नहीं हो सकता, क्या यह भुगतान प्रणाली की खामी है? या स्थानीय स्तर का व्यक्तिगत टकराव? या समूह राजनीति का असर? इन सवालियों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे।

आर्थिक और सामाजिक असर

आवेदिका ने अपने आवेदन में खुद को गरीब वर्ग की महिला बताते हुए आर्थिक तंगी का जिक्र किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में 20-22 हजार रुपये की राशि किसी परिवार के लिए कई महीनों की आजीविका का आधार हो सकती है, यदि आरोप सही हैं, तो यह मामला केवल भुगतान विवाद नहीं, बल्कि गरिमा और सुरक्षा का भी प्रश्न बन जाता है।

स्थानीय स्तर पर चर्चा

स्थानीय नागरिकों के अनुसार, स्कूल और समूह के बीच पहले भी मतभेद रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि विवाद व्यक्तिगत और प्रशासनिक खींचतान का परिणाम हो सकता है, वहीं कुछ का मानना है कि भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता की कमी ऐसी स्थितियों को जन्म देती है।

मनेन्द्रगढ़ सिविल अस्पताल का कार्याकल्प: 220 बिस्तरों के साथ बदली स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर

सीएचसी से 220 बेड सिविल अस्पताल तक का सफर, अब स्थानीय स्तर पर मिल रहा बेहतर इलाज, डायलासिस से सर्जरी तक सुविधा बढ़ी, मनेन्द्रगढ़ अस्पताल बना क्षेत्र का भरोसेमंद केंद्र



-संवाददाता-
एमसीबी/मनेन्द्रगढ़, 18 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

जिला मुख्यालय स्थित Government Civil Hospital Manendragarh का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) से उन्नयन कर 220 बिस्तरों सिविल अस्पताल के रूप में विकसित किया जाना क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, बड़ी हुई बेड क्षमता, विशेषज्ञ

चिकित्सकों की उपलब्धता, डायलासिस और सर्जिकल सेवाओं के विस्तार से अब मनेन्द्रगढ़ और आसपास के ग्रामीण अंचलों के मरीजों को बेहतर उपचार स्थानीय स्तर पर मिल रहा है, अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, बीते महीनों में चिकित्सा ढांचे को चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ किया गया है। इससे न केवल मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि रेफरल मामलों में भी कमी आई है। मनेन्द्रगढ़ का 220 बिस्तरों सिविल

अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं में सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बनता जा रहा है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता, सर्जिकल सेवाओं का विस्तार, डायलासिस और मातृत्व सुविधाओं की मजबूती ने स्थानीय स्तर पर भरोसा बढ़ाया है, यदि वर्तमान गति से विकास कार्य जारी रहे, तो यह अस्पताल न केवल एमसीबी जिले बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी एक भरोसेमंद और सुलभ स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है।



आईए चिकित्सा ढांचे को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं...



1. विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और 24 घंटे आपात सेवा

अस्पताल अधीक्षक डॉ. स्वप्निल तिवारी के अनुसार वर्तमान में अस्पताल में 15 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कार्यरत है, इनमें 3 मेडिकल स्पेशलिस्ट, 2 जनरल सर्जन, 2 नेत्र रोग विशेषज्ञ, 2 एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, अन्य विभागीय विशेषज्ञ इसके अतिरिक्त 10 से अधिक एमबीबीएस

चिकित्सक भी पदस्थ हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निदेशानुसार अस्पताल में सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। 24मई इमरजेंसी सेवा संचालित होने से सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, गंभीर संक्रमण और अन्य आपात मामलों में त्वरित उपचार संभव हो पा रहा है।

2. भवन विस्तार और बेड क्षमता में वृद्धि

220 बिस्तरों अस्पताल को पूर्ण क्षमता से संचालित करने के लिए अतिरिक्त भवनों का उपयोग किया जा रहा है, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और जनपद कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों में वाई विकसित किए जा रहे हैं, शासन स्तर से आवश्यक उन्नयन और संचालन के लिए राशि स्वीकृत की गई है, अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि आगे दो महीनों में 220 बिस्तरों की पूरी क्षमता के साथ अस्पताल नियमित रूप से कार्य करने लगेगा। इससे भर्ती मरीजों को पर्याप्त सुविधा मिलेगी।

3. स्त्री रोग विशेषज्ञ की कमी-समाधान की दिशा में पहल

वर्तमान में अस्पताल में एक ही स्त्री रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं, उनके अवकाश या व्यस्तता की स्थिति में असुविधा उत्पन्न होती है, सीएमएचओ डॉ. अविनाश खरे के प्रयासों से एक और स्त्री रोग विशेषज्ञ की ज्वाइनिंग शीघ्र प्रस्तावित है, आवश्यकता पड़ने पर जिला अस्पताल से डॉक्टर बुलाकर सेवाएँ सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि गर्भवती महिलाओं को समय पर और सुरक्षित उपचार मिल सके।

4. सर्जिकल सेवाओं का विस्तार,

अस्पताल में अब नियमित रूप से विभिन्न विभागों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, हाल के प्रमुख ऑपरेशन-
ENT विभाग
Bilateral Ear Lobe Repair
Malignancy True Cut Biopsy
ऑर्थोपेडिक विभाग
Humerus Nail Implant Removal
Tibia Nail Implant Removal
जनरल सर्जरी Hernioplasty
Lipoma E&cision
इन सर्जिकल सेवाओं के स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने से मरीजों को संभागीय मुख्यालय या निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम करनी पड़ी है।

6. डायलासिस और मातृत्व सेवाओं से मिली राहत

डायलासिस सुविधा ने किडनी मरीजों को बड़ी राहत दी है, पहले उन्हें दूर शहरों में जाकर महंगे निजी केंद्रों पर उपचार कराना पड़ता था, इसी प्रकार, प्रसूति और ऑपरेशन की स्थानीय सुविधा से गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में उपचार मिल रहा है, सामान्य और सिजेरियन दोनों प्रकार के प्रसव की सुविधा उपलब्ध है।

7. स्थानीय स्तर पर उपचार, रेफरल में कमी

अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्नयन के बाद गंभीर मामलों को बाहर रेफर करने की आवश्यकता में कमी आई है, लक्ष्य है कि अधिकतम मरीजों का उपचार मनेन्द्रगढ़ में ही हो सके, यदि 220 बिस्तरों क्षमता पूरी तरह संचालित हो जाती है, तो यह अस्पताल जिले के लिए मिनी-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में स्थापित हो सकता है।

5. उपलब्धियों के आंकड़े

(अप्रैल 2025-जनवरी 2026) अस्पताल की प्रगति निम्न आंकड़ों से स्पष्ट होती है-
कुल ओपीडी मरीज: 91,254
कुल आईपीडी मरीज: 6,029
डायलासिस सत्र: 4,087
सामान्य प्रसव: 975
सी-सेक्शन: 134
हड्डी रोग ऑपरेशन: 18
सामान्य सर्जरी: 54
ENT ऑपरेशन: 5

रक्त सेवा: 356 मरीजों को ब्लड उपलब्ध थे आंकड़े दर्शाते हैं कि अस्पताल अब बहु-विशेषज्ञता सेवाओं वाला एक सशक्त स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है।

8. स्वास्थ्य मंत्री की प्राथमिकता:
जिला स्तर पर मजबूत स्वास्थ्य ढांचा

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की सोच है कि जिला और उपजिला स्तर के अस्पतालों को मजबूत किया जाए, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े, विभागीय बैठकों में डॉक्टरों की नियुक्ति, दवाओं की उपलब्धता, उपकरणों की आपूर्ति और जांच सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मनेन्द्रगढ़ का सिविल अस्पताल इसी मॉडल का एक उदाहरण माना जा रहा है।

9. लोगों की प्रतिक्रियाएं

अस्पताल के उन्नयन के बाद स्थानीय नागरिकों और मरीजों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से परामर्श जल्दी मिल रहा है, डायलासिस सुविधा से आर्थिक बोझ कम हुआ है, अब छोटी सर्जरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ और बढ़ जाएं तो महिलाओं को और राहत मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों का कहना है कि बेड क्षमता बढ़ने से भर्ती प्रक्रिया आसान हुई है।

10. आगे की अपेक्षाएं

जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि, आधुनिक जांच मशीनों की स्थापना, नियमित सुपर स्पेशलिटी विजिट, मजबूत ब्लड बैंक, डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली से अस्पताल की सेवाएं और सुदृढ़ हो सकती हैं।

कोरिया में गूंजा स्वागत का शंखनाद...मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दौरे ने भरा संगठन में नया उत्साह

सड़क मार्ग से पहुंचे मुख्यमंत्री,कार्यकर्ताओं ने फूलों की वर्षा से किया ऐतिहासिक स्वागत...

- 92 वर्षीय मीसाबंदी से मुलाकात,कार्यकर्ताओं का सम्मान कोरिया प्रवास बना भावनाओं और विकास संकल्प का संगम
- भाजपा कार्यकर्ताओं की एकजुटता का प्रदर्शन: कोरिया में मुख्यमंत्री साय का भव्य अभिनंदन
- जनसंवाद,श्रद्धांजलि और विकास घोषणाओं के बीच कोरिया में मुख्यमंत्री साय का प्रभावशाली दौरा



रवि सिंह

कोरिया, 18 फरवरी 2026

(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कोरिया जिला प्रवास राजनीतिक,संगठनात्मक और भावनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, मूल रूप से हेलीकॉप्टर से आगमन का कार्यक्रम निर्धारित था, किंतु अंतिम समय में परिवर्तन होने के कारण मुख्यमंत्री को चिरमिरी से सड़क मार्ग द्वारा बैकटपुर पहुंचना पड़ा, कार्यक्रम में बदलाव के बावजूद कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई-बल्कि सड़क मार्ग से आगमन ने जगह-जगह स्वागत के अतिरिक्त अवसर प्रदान कर दिए।

बैकटपुर विश्राम गृह: अनुशासित स्वागत और आत्मीय संवाद

बैकटपुर स्थित विश्राम गृह में भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी,मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ कार्यकर्ता कतारबद्ध खड़े रहे, मुख्यमंत्री के पहुंचते ही पुष्पगुच्छ और महामालाओं से स्वागत किया गया,मुख्यमंत्री ने औपचारिकता से आगे बढ़ते हुए प्रत्येक

92 वर्षीय मीसाबंदी डॉ. निर्मल कुमार घोष से भावुक भेंट

मुख्यमंत्री का काफिला इसके बाद वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता एवं मीसाबंदी डॉ. निर्मल कुमार घोष के निवास पहुंचा, 92 वर्षीय डॉ. घोष से मुलाकात अत्यंत भावुक क्षणों से भरी रही, डॉ. घोष ने आपातकाल के समय के अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया गया। उन्होंने जिले के समग्र विकास-विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाओं और युवाओं के रोजगार-को लेकर सुझाव भी दिए,मुख्यमंत्री ने आदरपूर्वक उनकी बातें सुनीं और कहा कि 'आप जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं के त्याग और संघर्ष की बदौलत आज पार्टी जनविश्वास अर्जित कर पाई है, सरकार का हर प्रयास कार्यकर्ताओं के सपनों को साकार करने की दिशा में है,डॉ. घोष की पुत्री सुवर्णा द्वारा पारंपरिक तिलक और स्वागत ने वातावरण को आत्मीय बना दिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं में इस भेंट को लेकर विशेष उत्साह देखा गया।

पदाधिकारी से व्यक्तिगत परिचय लिया, उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों, बूथ स्तर की मजबूती और आगामी योजनाओं पर सक्षिप्त चर्चा की। उनका संदेश स्पष्ट था-‘संगठन ही शक्ति है, और कार्यकर्ता ही पार्टी की आत्मा।’

रविवीर फलेन्द्र सिंह को श्रद्धांजलि: विरसत का समान

इसके पश्चात मुख्यमंत्री ग्राम सरभोका पहुंचे, जहाँ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय फलेन्द्र सिंह की प्रतिमा पर

पुष्पांजलि अर्पित की गई, उन्होंने परिवारजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त की और कहा कि पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के योगदान को सदैव स्मरण रखती है,उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जिले के विकास कार्यों की रूपरेखा पर प्रकाश डाला और भरोसा दिलाया कि कोरिया को विकास की मुख्यधारा में अग्रणी बनाया जाएगा।

कृष्ण बिहारी जायसवाल के निवास पर श्रद्धांजलि-मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल के

झुमका डेम पर समाज प्रमुखों से संवाद

मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव झुमका डेम रहा, जहाँ जिले के विभिन्न समाज प्रमुखों से विस्तृत चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि चौमुखी विकास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी से संभव है,शिक्षा,स्वास्थ्य,जल प्रबंधन और स्थानीय रोजगार के मुद्दों पर समाज प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखीं,जिन्हें मुख्यमंत्री ने गंभीरता से नोट किया,यह बैठक केवल औपचारिक संवाद नहीं रही,बल्कि स्थानीय अपेक्षाओं और सरकार की प्राथमिकताओं के बीच सेतु का कार्य करती दिखाई दी।

17 फरवरी की सुबह: प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात

अगले दिन प्रातः स्थानीय विश्राम गृह में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की,किसानों,व्यापारियों,सामाजिक संगठनों और युवा प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी मांगें रखीं,मुख्यमंत्री ने आश्चर्य किया कि प्राथमिकता के आधार पर मांगों पर कार्यवाही की जाएगी,इसके बाद वे जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पारख के निवास पहुंचे,जहाँ कोरिया सेवा सदन में परिजनों और पार्टी कार्यकर्ताओं से आत्मीय संवाद हुआ।

निवास पहुंचे और उनके स्वर्गीय पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की,इस अवसर पर संगठनात्मक मजबूती,आगामी कार्यक्रमों और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा हुई, मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन की जड़ों को मजबूत रखने में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की

महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनसभा में उमड़ा जनसैलाब : जनसभा स्थल पर सभी मोर्चा और मंडलों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का महामालाओं से भव्य स्वागत किया, सभा 'मुख्यमंत्री साय जिंदबाद' के नारों से गूंज उठी, प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम,

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्थानीय विधायक भैया लाल राजवाड़े ने सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी, जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी, निवृत्तिमान जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल सहित सभी पदाधिकारी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से उपस्थित रहे।

संगठन, संवेदना और विकास का संदेश : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का यह कोरिया प्रवास केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मान, समाज प्रमुखों से संवाद, प्रतिनिधिमंडलों की समस्याओं को सुनना और जनसभा के माध्यम से विकास संकल्प को दोहराना-इन सभी ने मिलकर इस दौर को व्यापक आयाम दिया, कार्यकर्ताओं के उत्साह, आमजन की भागीदारी और नेतृत्व की संवेदनशीलता ने यह संदेश दिया कि कोरिया जिले में संगठन और सरकार दोनों विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं, यह प्रवास राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ भावनात्मक जुड़व और जनसंवाद का भी प्रतीक बन गया।

कोरिया महोत्सव की रोशनी में छुपा अंधेरा..भीड़ बुलाई, फिर ग्रामीणों को भगवान भरोसे छोड़ा

तालियाँ बजवाकर 'डीजल खत्म': महोत्सव खत्म होते ही प्रशासन की संवेदनशीलता भी हुई रवाना

भीड़ जुटी,मंच सजा...पर घर लौटने को तरसे वनांचल के ग्रामीण-जिम्मेदार कौन?

महोत्सव में विकास के भाषण,बाहर भूखे-प्यासे भटकते बच्चे-कोरिया प्रशासन कटघरे में...

हेलीकॉप्टर उड़ा,व्यवस्था भी उड़ गई: कोरिया महोत्सव बना कुप्रबंधन का आईना...

‘आओ तालियाँ बजाओ,फिर अपने हाल पर जाओ’-कोरिया महोत्सव पर बड़ा सवाल

रवि सिंह

कोरिया 18 फरवरी 2026

(घटती-घटना)।

तीन दिवसीय 'कोरिया महोत्सव' का शुभारंभ रोशनी, रंगमंच और भाषणों की ऊँची उड़ान के साथ हुआ, मंच सजा, कैमरे चमके, तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी और विकास के वादों ने आसमान छू लिया, मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुखिया विष्णु देव साय की उपस्थिति ने आयोजन को और भव्य बना दिया, लेकिन महोत्सव की चमक जब शाम के अंधेरे में ढली, तब स्टेडियम के बाहर एक दूसरी कहानी शुरू हुई-वो कहानी जो मंच की रोशनी में नहीं दिखती, पर प्रशासन की साख पर गहरा साया छोड़ जाती है।

भीड़ प्रबंधन या भीड़ प्रदर्शन? सूत्रों के अनुसार, सोनहत वनांचल के दूरस्थ ग्राम मधला और पुरसला सहित कई गांवों से ग्रामीणों को बसों में भरकर कार्यक्रम में लाया गया, बताया गया कि 'विकास की तस्वीर' दिखानी है, 'ऐतिहासिक आयोजन' का हिस्सा बनना है, ग्रामीण आए-महिलाएं आईं, बुजुर्ग आए, बच्चे आए, तालियाँ भी बजीं। मंच से विकास की गाथाएं भी सुनाई गईं, फिर हेलीकॉप्टर उड़ा... और कथित तौर पर व्यवस्थाओं की हवा भी साथ उड़ गई।

'डीजल खत्म है, किराया खुद दो'—व्यवस्था का नया मॉडल? जब



कार्यक्रम समाप्त हुआ और ग्रामीणों ने वापसी के लिए बसों का रुख किया, तो आरोप है कि जवाब मिला-‘बस में डीजल नहीं है, अपने खर्च से किराया दो।’ अब यह स्पष्ट नहीं कि डीजल सचमुच खत्म था या संवेदनशीलता, लेकिन इतना जरूर था कि ग्रामीणों की जब पहले से ही खाली थी, वे किसी सैर-सपाटे पर नहीं आए थे; उन्हें बुलाया गया था, ऐसा लगा मानो महोत्सव का असली संदेश यही था- ‘आओ, तालियाँ बजाओ... और फिर अपने भरोसे घर जाओ।’

भूखे-प्यासे इंतजार में बीती शाम- शाम ढली,रोशनी कम हुई,मंच सिमटा, लेकिन बसों के पास खड़ी महिलाएं और बिलखते बच्चे वहीं रहे, न भोजन की

व्यवस्था, न पानी का इंतजाम,न स्पष्ट सूचना, वनांचल से आए इन ग्रामीणों के लिए जिला मुख्यालय की भीड़ एक भूलभुलैया बन गई, उत्सव के अंदर 'सांस्कृतिक कार्यक्रम' चल रहे थे, बाहर 'संवेदनहीनता का लाइव प्रदर्शन'।

जब प्रशासन मौन, तब समाजसेवा सक्रिय- इस बीच जनहित संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष एस.के. रूप मौके पर पहुंचे, उन्होंने ग्रामीणों के लिए नाश्ता और जलपान की व्यवस्था कराई तथा बस किराए की राशि उपलब्ध कराकर उन्हें सुरक्षित गांव रवाना कराया, यानी जहां सरकारी तंत्र 'महोत्सव मोड' में था, वहां नागरिक पहल ने स्थिति संभाली।

सवाल जो तालियों में दब गए...

- यदि बसों का अधिग्रहण हुआ था, तो वापसी की योजना कहां थी?
- क्या भीड़ जुटाना ही अंतिम लक्ष्य था?
- क्या ग्रामीण केवल फोटो फ्रेम की पुच्छभूमि थे?

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? कहा जाता है कि बड़े आयोजनों में छोटी चूकें हो जाती हैं, पर जब 'छोटी चूक' भूखे-प्यासे भटकते बच्चों और असहाय महिलाओं में बदल जाए, तो वह चूक नहीं, चरित्र का प्रतिबिंब बन जाती है।

उत्सव बनाम उत्तरदायित्व- 'कोरिया महोत्सव' का उद्देश्य जिले की सांस्कृतिक पहचान और विकास को प्रदर्शित करना था, लेकिन यदि आयोजन के बाद वही लोग असहाय छोड़ दिए जाएं जिनके नाम पर विकास के दावे किए जाते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, व्यंग्य यही है कि मंच पर 'समावेशी विकास' की बातें हुईं और मंच के बाहर 'समावेशी उपेक्षा' का प्रदर्शन, अब देखना यह है कि प्रशासन इस घटना को 'समन्वय की कमी' कहकर फाइलों में दबा देता है या जिम्मेदारी तय कर वास्तविक सुधार की पहल करता है, क्योंकि उत्सव की असली परीक्षा रोशनी में नहीं,अंधेरे में होती है।

सूरजपुर में जहरीली गैस से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत

प्रधानमंत्री आवास की बनावट पर सवाल,ग्राम चंद्रपुर में पसरा मातम



-संवाददाता-

सूरजपुर, 18 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से सामने आई एक हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चंद्रपुर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई,मृतकों में पति-पत्नी और उनकी मासूम बेटी शामिल हैं। रात में जो परिवार हसते-बोलते भोजन कर सोया था, सुबह वही घर चीख-पुकार और सन्नाटे में डूब गया।

क्या हुआ उस रात?— प्रास जानकारी के अनुसार चंद्रपुर निवासी कवल सिंह (28 वर्ष), उनकी पत्नी कुंती (25 वर्ष) और लगभग चार वर्षीय बेटी मामत रात में खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो गए थे, कमरे के भीतर सिंगड़ी में कोयला जल रहा था, आशंका जताई जा रही है कि उसी सिंगड़ी से निकली जहरीली गैस-संभवतः कार्बन मोनोऑक्साइड-धीरे-धीरे पूरे कमरे में भर गई, दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के कारण धुआं बाहर नहीं निकल पाया और दम घुटने से तीनों की मौत हो गई, सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शंका हुई, दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो पूरा परिवार अचेत अवस्था में पड़ा था।

दो बच्चों की बची जान- बताया जा रहा है कि परिवार के दो अन्य बच्चे-प्रिंस (7 वर्ष) और प्राची (5 वर्ष)-उस रात अपने नाना के साथ घर के दूसरे हिस्से में सो रहे थे, इसी कारण उनकी जान बच गई, अब यही दो मासूम बच्चे इस त्रासदी के बीच अकेले खड़े हैं, गांव में हर जुबान पर एक ही सवाल है-इन बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा?

प्राथमिक जांच क्या कहती है?— पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में जहरीली गैस से दम घुटने की आशंका जताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा, विशेषज्ञों के अनुसार बंद कमरे में कोयला या सिंगड़ी जलाकर सोना बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड

गैस रंगहीन और गंधहीन होती है-जिसका अहसास होने तक बहुत देर हो जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना पर उठे सवाल- ग्रामीणों का कहना है कि मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था, लेकिन उसमें पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं था, गांव के लोगों का आरोप है: कमरे में रोशनदान की कमी थी, खिड़कियां छोटी या अपर्याप्त थीं, हवा के निकास की उचित व्यवस्था नहीं थी, यदि पर्याप्त वेंटिलेशन होता तो संभव है कि गैस बाहर निकल जाती और यह हादसा टल जाता। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि क्षेत्र में बने कई आवासों में तकनीकी खामियां हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए।

प्रशासन से मुआवजे की मांग- परिवार के परिजन प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि परिवार मेहनत-मजदूरी कर जीवनयापन करता था, एक ही इन्कटे में तीन जिंदगियां चली गईं, अब दो मासूम बच्चों की परवरिश, शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी किसकी होगी? यही सवाल पूरे गांव में गूंज रहा है।

यह सिर्फ हादसा नहीं, चेतावनी भी- यह घटना केवल एक परिवार का त्रासदी नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और निर्माण मानकों की समीक्षा की जरूरत की ओर भी इशारा करती है, सर्दियों में सिंगड़ी या कोयला जलाकर बंद कमरे में सोना जानलेवा साबित हो सकता है, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इसके खतरों के बारे में जानकारी दें, साथ ही, जिन घरों में वेंटिलेशन की कमी है, वहां तकनीकी सुधार के निर्देश जारी किए जाएं।

गांव में पसरा सन्नाटा- चंद्रपुर गांव में फिलहाल मातम का माहौल है, घर के बाहर बैठी बूढ़ी मां की सुनी आंखें और बिलखते परिजन इस त्रासदी की गवाही दे रहे हैं, एक छोटी सी चूक, या व्यवस्था की कमी-तीन जिंदगियां लील गईं, अब नजरों प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं-क्या जांच के बाद जवाबदेही तय होगी?

